



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 2008/फाल्गुन 20, 1929

No. 85]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 10, 2008/PHALGUNA 20, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2008

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : ई यू (फ्रांस को छोड़कर), इंडोनेशिया तथा चीनी ताइपेई के मूल के या वहाँ से निर्यातित कॉस्टिक सोडा के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा ।

सं. 15/11/2008-डीजीएडी.—यतः वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 8-1-2003 की अधिसूचना सं. 14/39/2002-डी जी ए डी द्वारा अर्न्तित शुल्क की सिफारिश की थी और 27 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 48/2003 के तहत भारत सरकार द्वारा अर्न्तित शुल्क लगाया गया था । प्राधिकारी ने ई यू (फ्रांस को छोड़कर), इंडोनेशिया तथा चीनी ताइपेई (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहाँ से निर्यातित कॉस्टिक सोडा (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 1-10-2003 की अधिसूचना सं. 14/39/2002-डी जी ए डी के द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे । दिनांक 14-11-2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 168/2003 के द्वारा भारत सरकार ने ऐसा निश्चयात्मक शुल्क लगाया था। प्राधिकारी ने मध्यावधि समीक्षा भी शुरू की और मध्यावधि समीक्षा जाँच परिणामों में अपनी दिनांक 2-6-2006 की अधिसूचना सं. 15/5/2005-डी जी ए डी के जरिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की और सरकार द्वारा 10-7-2006 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 72/2006 के जरिए ऐसा निश्चयात्मक शुल्क लगाया था ।

2. विचाराधीन उत्पाद :

मूल जांच, मध्यावधि समीक्षा और इस निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद ई यू (फ्रांस को छोड़कर), इंडोनेशिया और चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सोडियम हाइड्रोक्साइड (एन ए ओ एच) है जिसे आमतौर पर कॉस्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। कॉस्टिक सोडा एक अकार्बनिक, साबुन-जैसा और अत्यधिक क्षारीय गंधहीन रसायन है। कॉस्टिक सोडा का उपयोग लुगदी एवं कागज के विनिर्माण न्यूजप्रिंट, विस्कस यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्युमीनियम, कॉटन, वस्त्र, प्रसाधन एवं धुलाई के साबुन, डिटरजेंट, रंजकों, औषधियों एवं भेषजों, पेट्रोलियम प्रसंस्करण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में होता है। कॉस्टिक सोडा का उत्पादन दो रूपों में किया जाता है और यह दो रूपों अर्थात् लाई एवं ठोस में उपलब्ध है। वर्तमान जाँच में कॉस्टिक सोडा के सभी रूप शामिल हैं।

कॉस्टिक सोडा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 28 के तहत वर्गीकृत है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण [सुमेलीकृत वस्तु विवरण एवं कोडिंग प्रणाली] के अनुसार शीर्ष सं. 2815.11 तथा 2815.12 के अंतर्गत भी वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह वर्तमान जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

3. समीक्षा और जांच शुरूआत हेतु अनुरोध :

और जबकि सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 के अनुसार, लागू पाटनरोधी शुल्क को जब तक पहले हटाया न जाए, उसे लागू करने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर अप्रभावी हो जाता है।

और जबकि संबंधित नियमावली में प्राधिकारी के लिए पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करना अपेक्षित है और यदि वह उन्हें प्राप्त सूचना के आधार पर इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे शुल्क को लागू रखने का कोई औचित्य नहीं है तो प्राधिकारी केन्द्र सरकार से इसे हटाने की सिफारिश कर सकते हैं। उपर्युक्त प्रावधानों के होते हुए भी प्राधिकारी के लिए उपायों की समाप्ति की तारीख से पहले तर्कसंगत अवधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

उपर्युक्त उपबंधों के अनुसार, घरेलू उद्योग की ओर से मै. अल्कली मैनुफेक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ए एम ए आई), दिल्ली द्वारा एक याचिका दायर की गई है और यह एसोसिएशन भारत में कास्टिक सोडा के अधिकांशतः सभी घरेलू विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करती है। घरेलू उत्पादकों अर्थात् मै. डी. सी. डब्ल्यू लि., मुम्बई, मै. डी सी एम श्री राम कन्सॉलीडेटेड लि., नई दिल्ली, मै. गुजरात अल्कलीज एण्ड कैमिकल्स लि., बड़ोदरा, मै. एस आई ई एल कैमिकल्स काम्प्लैक्स, नई दिल्ली द्वारा इस याचिका का समर्थन किया गया है। उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अनुसार याचिकाकर्ताओं के पास घरेलू उद्योग की ओर से पाटनरोधी जाँच हेतु मामला दायर करने संबंधी योग्यता है और वह विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित याचिका के साथ प्राधिकारी के पास आये हैं जिसमें संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर लागू पाटनरोधी शुल्क को आगे 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए लागू रखने और इसे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

याचिका की जांच के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी मानते हैं कि पहले से लागू पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने से पाटन की पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने के बारे में याचिकाकर्ता के दावे की जांच करने के लिए यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क (5) के उपबंधों के अंतर्गत इस स्तर पर लागू पाटनरोधी शुल्क हेतु इस स्तर पर निर्णायक समीक्षा प्रक्रियाएं शुरू करना उचित होगा।

4. शामिल देश :

इस जांच में शामिल देश ई यू (फ्रांस को छोड़कर), इंडोनेशिया और चीनी ताईपेई हैं।

5. जांच अवधि :

वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1-1-2007 से 31-12-2007 तक है। तथापि क्षति संबंधी विश्लेषण में वर्ष, 2004-05, 2005-06, 2006-07 और जाँच अवधि 1-1-2007 से 31-12-2007 तक की अवधि शामिल है।

6. दिनांक 1-10-2003 की अधिसूचना सं. 14/39/2002-डी जी ए डी के तहत जारी अंतिम जांच परिणाम तथा दिनांक 14-11-2003 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 168/2003 के तहत लागू शुल्क के साथ-साथ दिनांक 2-6-2006 की अधिसूचना सं. 15/5/2005-डी जी ए डी के तहत जारी मध्यावधि समीक्षा परिणाम और दिनांक 10-7-2006 की अधिसूचना सं. 72/2006 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लागू निश्चयात्मक शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी इस बात की समीक्षा करने के लिए एतद्वारा जाँच शुरू करते हैं कि सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क का आकलन और वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से संबद्ध देशों के मूल के या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों का पाटन तथा क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना है। इस समीक्षा में दिनांक 8-1-2003 की जाँच शुरूआत अधिसूचना सं. 15/5/2005 और मूल जाँच के अंतिम परिणामों के साथ-साथ मध्यावधि समीक्षा के अंतिम परिणामों के सभी पहलू शामिल हों। प्राधिकारी का प्रस्ताव उपर्युक्त नियमों के अनुसार उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में यथा उल्लिखित आवेदक, जिसका भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है, को घरेलू उद्योग के रूप में मानने का है।

7. सूचना प्रदान करना :

संबद्ध देशों के निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, उत्पाद में संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और निम्नलिखित को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :-

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
कमरा सं. 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110001

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी जांच से संगत अपने अनुरोध निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से प्रस्तुत कर सकती है।

8. समय-सीमा :

वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई के लिए अनुरोध प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

9. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना :

नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पक्षों द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई किसी भी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सार प्रस्तुत करना अपेक्षित है और यदि ऐसी सूचना देने वाले पक्ष के अनुसार ऐसी सूचना का सार बनाना संभव नहीं है तो उसे इसका कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करना होगा।

10. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण :

नियम 6 (7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखते हैं। कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे हुए हैं। यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2008

(Sunset Review)

Sub : Sunset Review of Anti-dumping Duty imposed against Caustic Soda originating in or exported from EU (excluding France), Indonesia and Chinese Taipei.

No.15/11/2008-DGAD.—Whereas the Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of provisional duty *vide* Notification No. 14/39/2002-DGAD dated 8.1.2003 and such provisional duty was imposed by the Govt. of India *vide* Customs Notification No. 48/2003 dated 27.03.2003. The Authority issued its Final findings recommending imposition of definitive Anti-Dumping Duty on imports of Caustic Soda (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from EU (Excluding France), Indonesia and Chinese Taipei (hereinafter referred as subject countries), *vide* Notification No. 14/39/2002-DGAD dated 1-10-2003 and such definitive duty was imposed by the Government of India *vide* Customs Notification No. 168/2003 dated 14/11/2003. The Authority also initiated Mid Term Review and in Mid Term Review findings recommended imposition of definitive Anti-Dumping Duty *vide* Notification No.15/5/2005-DGAD dated 2-6-2006 and such definitive duty was imposed by the Government of India *vide* Customs Notification No.72/2006 dated 10-7-2006.

2. Product Under Consideration :

The product involved in the original investigation, Mid Term Review and this Sunset Review is Sodium Hydroxide (NaOH), commonly known as Caustic Soda originating in or exported from EU (excluding France), Indonesia and Chinese Taipei. Caustic Soda is an inorganic, soapy and strongly alkaline odourless chemical. Caustic Soda finds application in various fields like manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fibre, aluminium, cotton, textiles, toilet and laundry soaps, detergents, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, petroleum refining, etc.. Caustic soda is produced and available in two forms, i.e. Lye and solids. Present investigation covers all forms of Caustic Soda.

Caustic Soda is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975. It is further classified as per International Trade Classification [based on Harmonized Commodity Description and Coding System] under the heading 2815.11 and 2815.12. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

3. Request for Review and Initiation :

And whereas in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 the Anti-Dumping Duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.

And whereas the Rules *supra* require the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of Anti-Dumping Duty and if it is satisfied, on the basis of information received by it that there is no justification for continued imposition of such duty, the authority may recommend to the Central Government for its withdrawal. Notwithstanding the above provisions, the authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

In terms of the above provisions, a petition has been filed by M/s. Alkali Manufacturers Association of India (AMAI), Delhi on behalf of the domestic industry and the Association represents most of all the domestic manufacturers of Caustic Soda in India. The petition has been expressly supported by the domestic producers, viz. M/s. DCW Ltd., Mumbai, M/DCM Shriram Consolidated Ltd. New Delhi, M/s. Gujarat Alkalies & Chemicals Ltd., Vadodara, M/s. SIEL Chemicals Complex, New Delhi. As per the evidence available, petitioners have the standing to file the case for anti-dumping investigation on behalf of domestic industry as per rule 5 of Anti-Dumping Rules and has approached the authority with a duly substantiated petition requesting for continuation and enhancement of the Anti-Dumping Duty imposed on subject goods from subject countries for a further period of 5 (five) years.

On the basis of the examination of the petition, the Designated Authority considers that the Sunset Review proceedings for the Anti-Dumping Duty in force would be appropriate at this stage under the provisions of Section 9A(5) of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 as amended to investigate the claim of the petitioner about reoccurrence of dumping and consequential injury to the domestic industry in case of cessation of Anti-Dumping Duty already in place.

4. Countries involved :

The countries involved in this investigation are EU (Excluding France), Indonesia and Chinese Taipei.

5. Period of Investigation :

The Period of Investigation for the purpose of the present review is from 1-1-2007 to 31-12-2007. However, injury analysis shall cover the years 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 and Period of Investigation 1-1-2007 to 31-12-2007.

6. Procedure :

Having decided to review Final Findings issued *vide* Notification No.14/39/2002-DGAD dated 1.10.2003 and duty imposed *vide* Customs Notification No. 168/2003 dated 14-11-2003 as well as Mid Term Review Findings issued *vide* Notification No.15/5/2005-DGAD dated 2-6-2006 and definitive duty as imposed by the Government of India *vide* Notification No.72/2006 dated 10.7.2006 the Authority hereby initiates investigations to review whether cessation of Anti-Dumping Duty is likely to lead to recurrence of Dumping and Injury on imports of subject goods originating in or exported from subject countries in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. The review covers all aspects of Initiation Notification No.14/39/2002-DGAD dated 8-1-2003 and Initiation Notification No.15/5/2005 dated 3.6.2005 and Final Findings of the original investigations as well as Mid Term Review Final Findings. The Authority proposes to consider petitioner as mentioned in paragraph 3 above as domestic industry in accordance with the Rules *supra* as it constitutes the major proportion of the production of the subject goods in India.

7. Submission of Information :

The exporters in subject countries, the Governments of subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry, are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
The Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Department of Commerce,
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110001.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

8. Time Limit :

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules *supra*.

9. Submission of Information on Non-confidential basis :

In terms of Rule 7 the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary, a statement of reasons thereof is required to be provided.

10. Inspection of public file :

Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties in terms of Rule 6 (7). In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority